भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषयः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबधित जुलाई, 2022 माह का मासिक सारांश।

<u>जल जीवन मिशन (जेजेएम) में प्रगति</u>

19,20,436 परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1,716.64 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

<u>स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण चरण- II (एसबीएम (जी) में प्रगति</u>

1,91,726 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) और 1,779 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 88.31 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 9,165 गांवों ने ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी उपायों की सूचना दी जबकि 10,138 गांवों ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी उपायों की सूचना दी। 11,431 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित किया।

<u>स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा</u>

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने एसबीएम (जी) के तहत वर्ष 2022-23 में तिमाही प्रगति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिनांक 25.07.2022 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव और ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी मिशन निदेशकों के साथ बैठक की। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आवश्यक सलाह/सुझाव/अवलोकन दिए गए।

सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और घरेलू/समुदाय स्तर पर जल और स्वच्छता के प्रावधान के साथ इन्हें कम करने के लिए एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया।

भारत स्वच्छता संघ (आईएससी) के सहयोग से 75 मॉडल ओडीएफ प्लस ब्लॉक विकसित करने के लिए 29 जुलाई, 2022 को एक लाइटहाउस पहल शुरू की गई। इस कार्यक्रम में भारत सरकार, राज्य सरकारों, कॉर्पोरेट समूहों और स्वच्छता क्षेत्र में शामिल विकास भागीदारों के लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

जल जीवन मिशन की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने स्टील और धातु पाइप विनिर्माताओं, कार्यान्वयन एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ पाइप की उपलब्धता, उनकी कीमतों और अन्य मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए दिनांक 04.07.2022 को सचिव (इस्पात) के साथ एक बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की ताकि मिशन के निर्बाध कार्यान्वयन हेतु उनका उचित रूप से समाधान किया जा सके। पाइप निर्माताओं से अनुरोध किया गया कि वे भारत सरकार द्वारा विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण कीमतों में कमी का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं और इन्हें जीईएम पोर्टल पर ले आएं।

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने पाइपों की उपलब्धता, उनकी कीमतों, परीक्षण और अन्य मुद्दों के बारे में कार्यान्वयन एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ-साथ गैर-धातु पाइप विनिर्माताओं (पीवीसी, ओपीवीसी, एचडीपीई आदि) के साथ चर्चा करने के लिए दिनांक 06.07.2022 को सचिव (रसायन और पेट्रोरसायन) के साथ एक बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की ताकि मिशन के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए उनका उचित रूप से समाधान किया जा सके। पाइप विनिर्माताओं को बाजार में कीमतों में सुधार के लिए आयात शुल्क में कमी का लाभ ग्राहकों को देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पाइपों की परीक्षण अवधि को कम करने के लिए सीआईपीईटी से उनकी प्रयोगशाला परीक्षण क्षमता को इष्टतम करने का अनुरोध किया गया।

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों के संबंध में 13 फोकस राज्यों तथा शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एक अन्य एसीएस/प्रधान सचिव/ग्रामीण जल आपूर्ति/पीएचई विभागों के प्रभारी सचिव दिनांक 14.07.2022 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पीएचईडी अधिकारियों को "हर घर जल उत्सव" के बारे में जागरूक करने के लिए दिनांक 28.07.2022 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

पेयजल में यूरेनियम संदूषण की समस्या और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा करने के लिए 20 जुलाई, 2022 को एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। सचिव, डीडीडब्ल्यूएस और सचिव (डीएई) द्वारा बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की गई। निदेशक (बीएआरसी) और अपर सचिव एवं प्रबंध निदेशक, एनजेजेएम भी बैठक में उपस्थित थे।

एसबीएम (जी) के लिए क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

यूनिसेफ के सहयोग से 12 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में क्षमता निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर में स्वच्छता क्षेत्र में काम कर रहे 150 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों ने वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की। इसके बाद चुनौतियों और भावी कार्यनीति पर चर्चा हुई।

स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज

स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज के अंतिम दौर की बैठक 19-21 जुलाई, 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन प्रौद्योगिकियों की पहचान करना था जो ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) चुनौतियों के लिए टिकाऊ, किफायती, मापनीय (स्केलेबल) और उत्तरदायी समाधान में सहायक हो। शुरूआत में 300 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 62 को सूचीबद्ध किया गया और 43 को अंतिम दौर के लिए आमंत्रित किया गया। सभी श्रेणियों यंत्रीकृत मल सफाई (मैकेनाइज्ड डिसलजिंग), मलीय गाद प्रबंधन, गोबरधन, ग्रे वाटर प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, मासिक धर्म संबंधी प्रबंधन, ऑर्गेनिक कचरा प्रबंधन जो एसबीएम-जी चरण-II के तहत ओडीएफ प्लस के अभिन्न घटक हैं- में प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

परामर्शिका

एसबीएम (जी) चरण- II दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार एसबीएम (जी) के कार्यान्वयन में संबंधित जिले के सांसदों, विधायकों, एमएलसी की भागीदारी के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4 जुलाई, 2022 को एक परामर्शिका जारी की गई है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसबीएम (जी) चरण- II दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित नियमित आधार पर सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए 14 जुलाई, 2022 को एक और परामर्शिका जारी की गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए संग्रहण और पृथक्करण/भंडारण शेड/केंद्र के लिए एसबीएम (जी) निधियों के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए।

क्षेत्र दौरे

13-14 जुलाई, 2022 के दौरान, डीडीडब्ल्यूएस के सलाहकारों की टीमों ने ओडीएफ प्लस घोषणा की गुणवत्ता का आकलन करने तथा बड़े गांवों में सुजलम और एसएलडब्ल्यूएम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक,

मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु के चयनित जिलों के गांवों का दौरा किया। सलाहकारों की टीमों ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 19-23 जुलाई, 20-23 जुलाई और 27-31 जुलाई, 2022 के दौरान,क्रमशः छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान का दौरा किया।

आईआईटी रुड़की में कार्यशाला

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने आईआईटी रुड़की का दौरा किया और 1 जुलाई 2022 को "पेयजल और स्वच्छता: वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां" पर कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया। जल संसाधन विभाग, आईआईटी रुड़की का एक समृद्ध इतिहास है और यह अपने शोध कार्य के माध्यम से नीति और कार्यान्वयन में सहायता करने में एक अच्छी भूमिका निभा रहा है।

*****